संपादकीय

पाक में आतंक का मंसूबा

इसका ताजा उदाहरण वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला है। सब जानते हैं कि सेना प्रमुख से इमरान खान का मनमुटाव होने वजह से उनकी सरकार पलट दी गई थी। इस समय वे सत्ता के खिलाफ देश में विरोध मार्च निकाले हुए हैं। यह बात वहां के सेनाधिकारियों और खुफिया एजेंसी आइएसआइ को बुरी तरह खटक रही थी। बताया जा रहा है कि यह हमला उन्हीं के इशारे पर हुआ। गनीमत है कि गोली इमरान खान के पैर में लगी और वे बच गए। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई, वह उनके काफिले के साथ चल रहा था और उनके वाहन के करीब से अत्याधुनिक स्वचालित हथियार से गोली दागी। हालांकि यह समझना मुश्किल है कि उस काफिले की सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की खामी कैसे रखी गई कि कोई हथियारबंद आदमी पूर्व प्रधानमंत्री के वाहन के करीब तक पहुंच गया। पाकिस्तान अपने एक प्रधानमंत्री को ऐसी ही स्थितियों में खो चुका है, फिर भी उससे सबक लेना क्यों जरूरी नहीं समझा गया। मगर यह ज्यादा हैरानी का विषय इसलिए नहीं है कि जिन लोगों पर इमरान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब वही उनसे असहज महसूस कर रहे हैं, तो किसी हमलावर का उनके काफिले में घुस जाना कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता। दरअसल, इमरान खान अब तक के प्रधानमंत्रियों से अलग मिजाज के व्यक्ति हैं। अब तक वहां के प्रधानमंत्री एक तरह से सेना और आइएसआइ के इशारे पर चलते रहे हैं। वहां की सेना किस कदर ताकतवर है, यह सब जानते हैं। वह वहां की समांतर सत्ता की तरह काम करती है। जो प्रधानमंत्री उसके विरुद्ध जाने का प्रयास करता है, उसका तख्ता पलट करने में भी देर नहीं लगाती। मगर इमरान खान ने अनेक मौकों पर सेना की सलाह मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सेनाध्यक्ष और उनके बीच तल्खी बनी रही।दरअसल, इमरान खान पाकिस्तान की तरक्की के लिए योजनाएं बना रहे थे और इस क्रम में वे उन देशों से भी रिश्ते बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे, जिनसे कड़वाहट बनी रहती है। पाकिस्तानी सेना चूंकि अपनी सत्ता इसीलिए कायम रखे हुए है कि वह हर समय हिंदुस्तान से जंग का माहौल बनाए रखती है। यह माहौल वहां के हुक्मरानों को भी रास आता है, क्योंकि इससे उन्हें देश की बदहाली की तरफ देखने का मौका नहीं मिल पाता।इमरान खान देश के बुनियादी ढांचे को बदलना चाहते थे। इस तरह सेना की ताकत कम होती। इसीलिए इमरान खान की सरकार गिरा दी गई। अब जब उन्होंने देश की अवाम को सत्ता और सेना की हकीकत बताने के मकसद से विरोध मार्च निकाला, तो बताया जा रहा है कि उन्हें रास्ते से ही हटा देने की योजना बनाई गई। हालांकि हमलावर गिरफ्तार हो चुका है और उसका कहना है कि इमरान खान की बातों से वह परेशान हो उठा था। मगर दुनिया के सामने एक बार फिर वहां के निजाम की हकीकत खुल चुकी है। पता नहीं वहां की सेना और खुफिया एजेंसी कब इस बात को समझ पाएगी कि आतंकवाद का यह भस्मासुर उसके सिर पर भी हाथ रख सकता है।

इमरान पर हमला, पाकिस्तान अराजकता की तरफ

विशलेषण

आर.के. सिन्हा

इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान में अराजकता और अव्यवस्था व्यापक स्तर पर फैलने की आशंका है। इमरान पर हमले से पहले ही जनता सड़कों पर आ गई थी। अवाम का अपने मौजूदा कर्णधारों पर कोई यकीन नहीं हो पा रहा है। यह सबको पता है कि इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को सेना के जनरलों द्वारा जोड़-तोड़ करके हटवाया गया था। इसके बावजूद इमरान खान की तहरीके इंसाफ पार्टी (पीटीआई) की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश में सरकारें हैं। यानी इमरान खान की हैसियत कोई छोटी नहीं है। उनकी राजनीति ईमानदारी पर भी कोई शक नहीं कर सकता। इस मोर्चे पर उनका अभी तक का जीवन बेदाग सा ही रहा है।

पाकिस्तान में इमरान खान के सामने नवाज शरीफ, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ तथा आसिफ अली जरदारी हैं। इन सब पर अरबों रुपये के घोटाले के आरोप हैं। ये सब हजारों करोड़ की चल और अचल संपत्ति के मालिक भी हैं। शरीफ बंधु जनता को झूठे सब्जबाग दिखा कर ही अबतक चुनाव जीतते रहे हैं। ये घनघोर रूप से पतित और भ्रष्ट राजनीतिक हैं। नवाज ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कभी भी कोई सघन प्रयास नहीं किए। उनके समय में पाकिस्तान में मुद्रास्फीति से अवाम का बुरा हाल था और देश में कहीं से कोई विदेशी निवेश नहीं आ रहा था। अब उनके अनुज शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं। वे करप्शन के आरोपों से में आकंठ डूबे हुए हैं। जरदारी साहब तो उससे भी महान हैं। उनके करप्शन के मामलों की गिनती करना तक एक कठिन काम है। यह वास्तव में पाकिस्तान की जनता के साथ अन्याय ही हो रहा है। शहबाज शरीफ की इमेज मुहाजिर विरोधी भी रही है। वे मुहाजिरों यानी भारत से जाकर पाकिस्तान में जा बसे मुसलमानों के खिलाफ हैं। उन्होंने एक बार मुहाजिरों पर एक सभा में तंज करते हुए कहा था कि वे (जो उत्तर प्रदेश-बिहार से 1947 में पाकिस्तान चले गए थे) पान खाने वाले कराची की तरह लाहौर को भी खूबसूरत बना देंगे। पान खाने वालों से उनका इशारा मुहाजिरों से ही था। शहबाज शरीफ पर यह भी आरोप हैं कि उन्होंने हाल ही में बाढ़ से बर्बाद पाकिस्तानियों के लिये कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में बाढ़ से 1000 से अधिक लोग मारे गये थे और लाखों बेघर हो गये थे। बाढ़ के चलते भारी संख्या में घर उजड़ गए, खेत तबाह हो गए और पेट्रोल पंप डूब गए। बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मचाई। देश का एक तिहाई हिस्सा बाढ़ में डूबा । बाढ़ ने पाकिस्तान में अनाज से लेकर पीने का पानी तक छीन लिया। सिंध और पंजाब में कपास की खेती बर्बाद हो गई। कपास की करीब 10 लाख एकड़ की फसल तबाह हुई। इसके अलावा, 6 लाख एकड़ में लगा हुआ धान, एक लाख एकड़ में लगा खजूर और करीब 7 लाख एकड़ में लगा गन्ना भी तबाह हुआ।

दरअसल पाकिस्तान में सरकारों का जनता के दुख-दर्द से कोई सरोकार नहीं रहा। उनका सारा फोकस रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना रहता है। उन्हें देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की रत्तीभर भी चिंता नहीं है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। शिक्षा और सेहत पर भी खर्च को लेकर किसी तरह की गंभीरता नजर नहीं आती। उन्हें तो अपना रक्षा बजट ही बढ़ाना और उसमें कमीशन खाना होता है। इसका एक उदाहरण ले लीजिए। पाकिस्तान ने चालू वित्त वर्ष का रक्षा बजट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 1523 अरब रुपये कर दिया है। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान सुधरने वाला मुल्क नहीं है। उसकी बुनियाद में ही नफरत है। वहां पर बाढ़ से तबाही आए या फिर कोई अन्य कारण रहे, पाकिस्तान का पागलपन जारी रहता है। पिछले 75 सालों में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया और पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़ा है। विकास से कोसों दूर बसती है पाकिस्तान की दुनिया। वहां न टूरिस्ट आते हैं और न ही विदेशी पूंजी निवेश। हां, पाकिस्तान ने अपने को आतंकवाद की फैक्टरी के रूप में जरूर स्थापित कर लिया है।

इस बीच, इमरान खान पर हमले पर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की 16 अक्तूबर, 1951 को रावलपिंडी में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वे एक सभा को संबोधित करने ही वाले थे। उन्होंने मंच पर आकर बोलना शुरू ही किया था कि उनके भाषण को सुनने आया एक शख्स अपनी जगह से उठा और उसने लियाकत अली खान को गोली मार दी। यह घटना रावलपिंडी के कंपनी बाग में हुई थी। उसे भी वहां ही सुरक्षा कर्मियों ने मार डाला। इसलिए कत्ल की गुत्थी कभी सुलझी ही नहीं। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद बेनजीर भुट्टो की हत्या रावलपिंडी में 27 दिसंबर, 2007 को हुई। बेनजीर भुट्टो पर हमला करने वाले आत्मघाती हमलावर की पहचान सईद बिलाल के रूप में हुई थी। उस केस का सच भी कभी सामने नहीं आया। हां, आरोप लगे थे तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ बेनजीर भुट्टो को मरवाना चाहते थे।

पाकिस्तान के 75 सालों के इतिहास में पहली बार खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ हत्या के प्रयास के कुछ घंटों बाद खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में कोर कमांडर हाउस के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इमरान पर हमले के पीछे आईएसआई चीफ मेजर जनरल फैसल का हाथ होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओर से इसे लेकर एक वीडियो शेयर किया गया है। इमरान की पार्टी के नेता कह रहे हैं- जब नॉन-पॉलिटिकल लोग राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जनता यह देखे कि इमरान खान को धमकी देने वालों के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में अविश्वास का माहौल पैदा होता है। इमरान खान के करीबी असद उमर ने कहा है कि उनका मानना है कि हमले में तीन लोग शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल शामिल हैं। उन्हें पहले भी इस बात की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर वो यह कह रहे हैं ।

एक बात साफ है कि इमरान खान शांत बैठने वाले शख्स तो नहीं हैं। वे लड़ाकू स्वभाव के मनुष्य हैं। वे अस्पताल से बाहर आने के बाद फिर से सड़कों पर उतरेंगे। वे देश में तुरंत संसद के चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें देश की जनता का साथ भी मिल रहा है। जब तक वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार सत्ता पर काबिज नहीं होती तब तक तो वहां पर अव्यवस्था बनी ही रहने वाली है। यह गंभीर स्थिति है। भारत को इस पर पैनी नजर रखनी होगी। विश्व बिरादरी को भी पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिए कोशिशें तो करनी ही चाहिए।

अतार्किक दोहन के खतरनाक नतीजे

मुद्दा

प्रह्लाद सबनानी

प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो बहुत आसानी से की जा सकती है, मगर इस दौर में जिस तरह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के उपयोग और संग्रहण की भूख लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें लोग प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने को मजबूर हो गए हैं। कहा जाता है कि जिस गति से विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, उसी गति से अगर विकासशील और अविकसित देश भी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने लगें तो इसके लिए केवल एक धरती से काम चलने वाला नहीं है। जल्दी ही हमें ऐसी चार पृथ्वी की आवश्यकता होगी। जिस गति से कोयला, गैस, तेल आदि संसाधनों का इस्तेमाल पूरे विश्व में किया जा रहा है, उसे देखते हुए आने वाले कुछ वर्षों में इनके भंडार समाप्त होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। 'बीपी स्टेटिस्टिकल रिव्यू आफ वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट 2016' के अनुसार दुनिया में जिस तेजी से गैस भंडार का इस्तेमाल हो रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही, तो प्राकृतिक गैस के भंडार आने वाले बावन वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन में कोयले के भंडार सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं।

मगर विकसित और विकासशील सहित तमाम देश जिस रफ्तार से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले एक सौ चौदह वर्षों में कोयले के भंडार दुनिया में समाप्त हो जाएंगे। एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति औसतन प्रतिमाह पंद्रह लीटर से अधिक तेल की खपत कर रहा है। धरती के पास अब केवल तिरपन सालों का भूमिगत तेल शेष है।

प्रकृति के अतार्किक दोहन का ही नतीजा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी बहुत तेजी से घटती जा रही है। पिछले चालीस वर्षों में कृषि योग्य तैंतीस फीसद भूमि या तो बंजर हो चुकी है या

उसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम हो गई है। इसके चलते पिछले बीस वर्षों में दुनिया में कृषि उत्पादकता लगभग बीस फीसद तक घट गई है। इस पृथ्वी के कुल पानी का 97.5 फीसद समुद्र में है, जो कि खारा है। 1.5 फीसद बर्फ के रूप में उपलब्ध है। केवल एक फीसद पानी पीने योग्य है। वर्ष 2025 तक भारत की आधी और दुनिया की 1.8 अरब आबादी के पास पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं होगा। यानी पीने के मीठे पानी का अकाल पड़ने की पूरी संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पीनी के पानी के लिए हर गांव, हर गली-मोहल्ले में पानी के लिए युद्ध होंगे। पर हम इसके बारे में अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं। आगे आने वाले समय में परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं।

कई पर्यावरणविदों का मत है कि पिछले चालीस साल से भी अधिक समय में वृक्षारोपण के नाम पर ऐसे वृक्ष देश में लगाए गए हैं, जो आज पर्यावरण की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बन गए हैं। इन वृक्षों के कारण जमीन में पानी का तेजी से क्षरण हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में चीड़ के करोड़ों वृक्ष लगाए गए हैं। चीड़ एक ऐसा वृक्ष है, जो बड़ी तेजी से भूमि के पानी को सुखा देता है। इसकी पत्तियों के विषैले प्रभाव से जंगल की लगभग सारी वनस्पतियां, पौधे और वृक्ष समाप्त हो जाते हैं।

इन वृक्षों के अत्यधिक ज्वलनशील पत्तों के कारण हर वर्ष जंगलों में आग लगने की बड़ी घटनाएं होती हैं। इसमें करोड़ों जीव मरते हैं, जंगल नष्ट होते और भूमि का जल सूख जाता है। सैकड़ों-हजारों साल में बने जंगलों पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके चलते करोड़ों एकड़ भूमि बंजर बन गई है। वनों की वर्षा जल को रोकने की क्षमता काफी क्षीण हो गई है। परिणामस्वरूप, वर्षाकाल में मैदानों में भयंकर बाढ़ आने लगी है। वनों की जल संग्रहण क्षमता समाप्त होने के कारण कई क्षेत्रों में सूखा पड़ता है, जल संकट होता है। हमारे सदा भरे रहने वाले नदी-नाले, चश्मे सूखने लगे हैं। फिर भी हम वृक्षारोपण के नाम पर चीड़ जैसे वृक्ष लगाते चले गए। हालांकि अब चीड़ के पेड़ लगाने की रफ्तार कम हुई है। पर सच तो यह है कि यह सब हमारी नासमझी का ही परिणाम है। बिना सोचे-समझे केवल विदेशों से आयातित योजनाओं या उनकी शरारतों का शिकार बन जाना भी आज की हमारी दुर्दशा के लिए एक जिम्मेदार कारक है। पर्यावरणविदों के अनुसार अब सीधा समाधान यही है कि जिस प्रकार हमने चीड़, पापुलर, युकेलिप्टिस, रोबीनिया, लुसीनिया, एलस्टोनिया, सिल्वर ओक, नकली अशोक, बाटलब्रश जैसे करोड़ों वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बर्बाद किया है, पानी की भयंकर कमी पैदा की है, उसी प्रकार अब हम ऐसे वृक्ष लगाएं, जो पानी को संग्रहित करते और वर्षा जल को रोकते हैं। इस श्रेणी में भारत में अनगिनत वृक्ष हैं, जो जल संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं।

इस प्रकार के वृक्षों में पहाड़ों के लिए बियूंस (विलो), बान, खरशू आदि बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इनमें बियूंस बहुत आसानी से लग जाता है। बरसात के मौसम में इसकी टहनियां काटकर गाड़ दी जाएं तो आसानी से जड़ें निकल आती है और वृक्ष बन जाता है। ऊंचाई पर देवदार, रखाल, बुरांस आदि वृक्ष लग सकते हैं। जल संग्रह के लिए इनकी क्षमता बहुत बढ़िया है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में पीपल, पिलखन, नीम, आम, जामुन आदि उत्तम पेड़ माने जाते हैं, तो रेतीली भूमि के लिए खेजड़ी, बबूल, कैर आदि जैसे पेड़ लाभदायक माने जाते हैं। मगर प्रकृति से दूरी और अपने देशी पेड़ पौधों के प्रति बेरुखी ने पूरे देश में प्रदूषण की समस्या को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत में अगर प्रदूषण की समस्या से निजात पाना है, तो फिर से नीम, पीपल, बरगद, जामुन और गूलर जैसे पेड़ों को विकसित करने के बारे में सोचना होगा। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में सामने आया है कि चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ सर्वाधिक मात्रा में धूलकणों का रोकते हैं, जिससे प्रदूषण रोकने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आमतौर पर भारत में पाए जाने वाले चौड़ी पत्तियों वाले पौधों का कैनोपी आर्किटेक्चर सड़कों के किनारे विकसित किया जाए तो प्रदूषण का स्तर काफी कम किया जा सकता है।

आजकल

भारत में शिक्षा की दुर्दशा

भारत में शिक्षा की कितनी दुर्दशा है, इसका पता यूनेस्को की एक ताजा रपट से चल रहा है। 75 साल की आजादी के बावजूद एशिया के छोटे-मोटे देशों के मुकाबले भारत क्यों पिछड़ा हुआ है, इसका मूल कारण यह है कि हमारी सरकारों ने शिक्षा और चिकित्सा पर कभी समुचित ध्यान दिया ही नहीं। इसीलिए देश के मुट्ठीभर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं। देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के बच्चे उचित शिक्षा-दीक्षा से और वे लोग पर्याप्त चिकित्सा से वंचित रहते हैं। यूनेस्को ने भारत में खोज-पड़ताल करके बताया है कि देश के 73 प्रतिशत माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पढ़ाई का स्तर घटिया होता है। वहां से पढ़े हुए बच्चों को ऊंची नौकरियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनका अंग्रेजी ज्ञान कमजोर होता है। हमारी सरकारों के निकम्मेपन के कारण आज तक सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे बड़े होकर या तो सरकारी नौकरियां हथियाने या फिर अमेरिका और कनाडा भागने के लिए आतुर रहते हैं। गैरसरकारी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की फीस 50-50 हजार रुपेय महीना तक है। आजकल अस्पताल और ये शिक्षा-संस्थाएं देश में ठगी के सबसे क्रूर ठिकाने बन गए हैं। देश के गरीब, ग्रामीण, पिछड़े और आदिवासी लोग समुचित शिक्षा और चिकित्सा के बिना ही अपना जीवन गुजारते रहते हैं। सरकारी स्कूल और अस्पताल भी उनकी सेवा सरल भाव से नहीं करते।

देश के 90 प्रतिशत स्कूल फीस वसूली के दम पर जिन्दा रहते हैं। देश में 29600 स्कूल ऐसे हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। 4 हजार से ज्यादा मदरसे भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन स्कूलों से निकलने वाले छात्र क्या नए भारत के निर्माण में कोई उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं यदि हम शिक्षा के मामले में भारत की तुलना दक्षेस के हमारे पड़ोसी सातों देशों से करें तो उक्त पैमाने पर वह अफगानिस्तान के सबसे करीब है लेकिन वह श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। प्राचीन भारत की शिक्षा-व्यवस्था जग प्रसिद्ध रही है। चीन, जापान और यूनान से सदियों पहले लोग भारत इसीलिए आया करते थे कि यहां की शिक्षा-प्रणाली उन्हें सर्वश्रेष्ठ लगा करती थी। आज अमेरिका दुनिया की सर्वोच्च महाशक्ति अपनी शिक्षा के दम पर बना है लेकिन भारत मैकाले की गुलामी में ही गुलछर्रे उड़ा रहा है। पता नहीं, आजादी के सौ साल तक भी इस सड़ी हुई शिक्षा-व्यवस्था को बदलने वाला कोई नेतृत्व भारत में पैदा होगा या नहीं ।

जिंदगी से मायूस होते लोग

सामयिक

संगीता सहाय

भारत में आत्महत्या करने वालों की संख्या हत्या में जान गंवाने वालों से पांच गुना अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में 1.39 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसमें सड़सठ फीसद अठारह से पैंतालीस साल की उम्र के बीच के लोग थे। आत्महत्या करने वालों में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

किसी न किसी व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया। से उनतीस साल की उम्र के लोग बड़ी संख्या में होते हैं। यानी ऊर्जा, उत्साह और सपनों से लबरेज उम्र में जिंदगी से पलायन एक भयानक सच्चाई है। महानगरों, बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गौरतलब है कि भारत में आत्महत्या की दर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा है। तेजी से शिक्षित और विकसित होते भारत में बढ़ती आत्महत्या की मनोवृत्ति से हमारी जीवन शैली, सोच, बदलता पारिवारिक और सामाजिक परिवेश, शिक्षा और रोजगार की स्थिति, व्यवस्था की फितरत सब पर एक प्रश्नवाचक चिह्न लगता है। जीवन सबको प्रिय होता है। व्यक्तिवादी होते इस दौर में तो स्वयं के प्रति मुग्धता और बढ़ी है। खुद के विकास, पहचान, महत्त्व के प्रति लोग पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं। समान्यतया लोग आज सबसे ज्यादा खुद की चिंता करते हैं, उसके बाद किसी और की। खासकर युवा अपने रहन-सहन, पहनावे आदि पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। 'मैं', 'मेरी पहचान', 'मेरी मर्जी' जैसे शब्द लगातार अहम होते जा रहे हैं। शायद इसी आत्ममुग्धता में आत्महत्या का बीज भी छिपा है। स्वयं के विकास की लगातार बढ़ती भूख में जहां 'मैं' का भाव बढ़ा है, वहीं लोगों को परिवार और सामाजिकता से दूर भी किया है। इससे व्यक्ति में अकेलापन बढ़ा है। वह अपनी समस्याएं किसी से साझा करने में कतराने लगा है। या फिर उसकी नजर में ऐसा कोई होता ही नहीं, जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। इससे हताशा बढ़ी है और आत्महत्या की दर भी। छोटे-बड़े शहरों, गांवों, घरों, कार्यस्थलों के साथ-साथ आइआइटी, आइआइएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति इसी ओर इशारा करती है। पिछले कुछ दशक से लोगों की इच्छाएं और उम्मीदें तेजी से बढ़ी हैं। सब कुछ मुट्ठी में कर लेने का दौर-सा चल पड़ा है। सामने वाला व्यक्ति इतना संपन्न हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं मैं सब कुछ क्यों नहीं पा सकता या जो चाहूं वह क्यों नहीं बन सकता जैसी बातें खूब होने लगी हैं। मगर इसके बरक्स अवसर उतने नहीं बढ़े हैं। उम्मीदों और यथार्थ के बीच बड़ा फर्क होता है।

ऐसे लोगों को एकांतवास नहीं, प्रेमिल साथ की आवश्यकता होती है। उनके मन की तहों को खोलने, उनके अंदर चल रहे विचारों के झंझावातों को जानने-समझने और नकारात्मकता को दूर करने की आवश्यकता है। तमाम कोशिशों के बावजूद खुदकुशी की प्रवृत्ति पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है। आत्महत्या करने वालों में किशोर, युवा, ढलती उम्र के लोग तक शामिल हैं। इसके पीछे कारोबार में विफलता, मानसिक अवसाद, प्रेम में विफलता, घरेलू कलह, गरीबी, कर्ज का चक्र आदि कई वजहें बताई जाती हैं। पर गहरी पड़ताल करने पर इन प्रत्यक्ष कारणों के अलावा कई अन्य परोक्ष कारण भी दिखाई पड़ते हैं। पर कारण कोई भी हो, जिंदगी से बड़ी और महत्त्वपूर्ण तो कोई चीज नहीं हो सकती। मगर रोजमर्रा की मुश्किलों और जद्दोजहद को लेकर जीवन की अंगुली ही छोड़ देना, किन मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक दुरूहताओं का परिणाम है यह प्रश्न विचारणीय है। भारत में आत्महत्या करने वालों की संख्या हत्या में जान गंवाने वालों से पांच गुना अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में 1.39 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसमें सड़सठ फीसद अठारह से पैंतालीस साल की उम्र के बीच के लोग थे। आत्महत्या करने वालों में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में हर चार मिनट में